







**संपादकीय**

आनी कठोर जीर्णे टॉलरेंस नीति के लिये कुछ्यात रहे चीन ने कोरोना विप्रकोट के बीच हाल ही में जो घोषणाएँ की हैं उनमें पूरी दुनिया को बौकाया है। ऐसे वक्त में जब गैर सरकारी सूचीं के हवाले से कुछ ही दिनों में कठोरों लोगों के संक्रमण होने की खबरें आ रही हैं, चीन सरकार के हालिया फैसले हरत में डालते हैं। दरअसल, कठोर कोविड नीति के खिलाफ उग्र आंदोलन के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आंदोलन के दमन के बजाय कोविड नीतियों में ढील देने का विकल्प तुरा। शायद वे इस आंदोलन को हवा नहीं दाना चाहते थे। दरअसल, चीन की जनता करीब तीन साल के सख्त प्रतिधियों से उकता गई थी। वहाँ लाग सामान्य जीवन के लिये तरस रहे थे। वहीं जीविका का बड़ा संकट भी पैदा हो गया। वैश्विक विरोध और विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते चीन बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बड़े उदाघ चीन से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में चीन की सरकार को लाता है कि सख्त कोविड नीतियों से एक तो कोरोना को हराया नहीं जा सका, वहीं करोबार के क्षेत्र में विक्री क्षमता पुढ़ रही है। यीहा बदल वे कि जिनपिंग ने अपनी कठोर नीतियों में अप्रारूपित बदलाव किया है। चीन ने कोरोना के उफान के बीच घोषणा की है कि वह 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये तमाम

भारत सहित दुनिया के कई देश इन दिनों कड़की की ठंड से कांप रहे हैं। भारत का उत्तर भाग जो जबरदस्त शीतल हल्ह का समाना कर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और राजस्थान में तो कई रस्तानों में रात का तापमान शूष्य डिग्री सेलिसियर के आसपास बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तो न्यूटनतम तापमान नैनीताल और धर्मशाला से भी नींवे उल रहा है। मालवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा तो नैनीताल में यह 7.2 डिग्री और धर्मशाला 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कठकों की ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पलटाड़ और ट्रोनों पर अपर पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दो जनवरी तक मौसम के ऐसे ही हालात बने रहने की घोषणा की है। न केवल भारत, बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी इन दिनों मौसम का कहर झल रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने बुरी तरह हल्कान हैं, वर्षीय तृफानों का समाना कर रहे हैं। बड़ा कंडे शहरों में लोगों का घर से निकलना तक दूब हो गया है। अनेक जगमानों पर बर्फ की कई इच्छाएँ वाली परत बिछ चुकी हैं। भारत में भी गुलर्मा और लाहौल स्पीति के ऊर्चाई वाले हिस्से बर्फ की चादर ओढ़ चुके हैं। मौसम का यह रूप अनेक लोगों को बैर सपाट का आनंद उठाने का मोका दिया है तो बड़ी तादाद में गरीबों और बिहारी का सांतन का भी काम करता है। एसएम वर्ग के लिए भी यहां कोहरा परेशानी का सबव बनता है। घने कोहरे से एकप्रसेस पर हाद्दों की संख्या बढ़ जाती है। मालवार को भी वाहनों के टकराने से पांच लोगों की मौत हुई और अंतें लोग घायल हो गए। घने कोहरे से ट्रोनों की आवाजाही में और पलाइटों की रवानी और आगमन में दिलव होती है। इसके अलावा, पांचर लाइनों में दिपिंग की समर्थना भी बढ़ जाती है। बैर लोगों, जो गर्मी में कही भी सो लेते हैं, को जाड़े में भारी समर्थनों का समाना करना पड़ता है। दिल्ली में वर्षमान में दो लाख से अधिक लोग बैर हैं। सरकार को इनके लिए रेवेसरों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होती है। इसके बावजूद बुरु से लोग रेवेसरों से बिहित रह जाते हैं। ठंड इनके लिए जानतेरों साक्षित होती है। इस मौसम में भी कुछ गरीबों की जान जा चुकी है। सरकार को बाहिर किए गए वह इन लोगों के लिए रहने, खोने और दवाओं विद्यादि की टोंस व्यवस्था कर ताकि ठंड

चिंतन-मनन

नानाप जागरण का गारना  
नालंदा तक्षशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालय इस देश में थे। देश की शिक्षा व्यवस्था की पूर्णता स्थानीय गुरुकुल ही कर लेते थे। उच्च स्तरीय एवं अंतरराष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का प्रबुद्ध यह विश्वविद्यालय करते थे। देश-देशसंतों की भाषाएं वहाँ पढ़ाई जाती थीं जिनमें पारंगत होकर अपने को विश्व सेवा के लिए समर्पित करने वाले महामानव विश्व के कोने-कोने में पिछड़े क्षेत्रों को पिछड़ी वर्षों को हर दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए अपनी अहंतुकी सेवा भावना की अजस्र बगा करते थे। न केवल धर्म और अध्यात्म दरन बुधि पृथग्यामी वृक्षशास्त्रण शिव उद्यग नालंदा का पिकित्सा बासु रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की अनेकानेक धाराओं से संसारावासियों को परिचय द्वीपीण करने के लिए अथक परिश्रम किया गया। फलतः मानव जाति को अपनी पिछड़ी हुई अभावग्रस्त एवं विप्र स्थिति से छुटकारा मिला। अत्र वस्त्र निवास और शिक्षा की आरभिक आवश्यकताएं पूरी होने पर प्राप्ति के

अन्याच्या मार्ग खुले।  
मुख्य जीवन की गिरामा दो पहिये के रथ पर घडकर गतिशील होती है। एक पहिये है आप निर्माण दूसरा लेक-निर्माण। यही दो लक्ष्य भारतीय संस्कृति के दो अवधिश्री अग रहे हैं। उग्र कर्म स्वभाव की दृष्टि से इस दशा के निवासी निरंतर प्रयत्नसंनिधि रहे हैं कि उक्ता व्यक्तिकृत सद्व्यवहारों और सत्त्वव्यवहारों से परिपूर्ण हों। उसे आसा और अनुकरणीय माना जाए। यही थी उन दिनों व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक महात्वाकांक्षा। भौतिक दृष्टि से हर व्यक्ति सम्पूर्णतः सुव्यवस्थित और साधन संपन्न जीवन जीता था और उक्तकृत विनां और आदर्श कर्तव्य हर किसी के लिए प्रगति का मामादण्ड बना हुआ था। भारतीय जीवन की दूसरा लक्ष्य था- लेक निर्माण। वह मनुष्य यथा जो अपनी उपलब्धियों से कंठ लग अपने शरीर और परिवार को ही लाभान्वित करे। ऐसे यौवन के गर्व से मिरोंगा- पिंजरोंगा था और यथार्थ-

लाना चाहिए। फर, बड़ा जाति पालन के लिए सभी नारे हुए—हुए और जनसंघ व लोगों ने उसके कृष्णी प्रकाश एवं सर्वशोधण्या प्राप्त न कर सके। उन दिनों यही लोक मान्यता थी कि हर समूहत व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति एवं विषयितों को एक बड़ा भाग समजन की उत्तमि में—सुख शांति की अभिवृद्धि में लगाना चाहिए, आत्मोक्षण्क की तरह लोक कल्याण भी मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतवासी की वैसी मान्यता निष्ठा और

# नेपाल की नई सरकार और भारत

भारत और नेपाल, दोनों समान संस्कृति और मूल्यों वाले पड़ोसी हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध निर्धारित दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो इसकी बड़ी वजह कहीं न कहीं नेपाल का चीन प्रेम ही है। ओली के समर्थन से बन रही नेपाल की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को किस तरह आगे बढ़ाती है, यह अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।



के लिए भारत के साथ तनाव को हवा देंगे। दूसरा, ओली की यीन परस्ती पहले से ही जा जानिर है। हालांकि, नेपाली कांग्रेस के साथ काम करते हुए प्रवर्द्ध के भारत विरोध रुख में बदलाव आया है। फिर भी सायल तो परेशान करता ही है कि अपर प्रबंध का यीन प्रेम जाग उठा तो भारत, नेपाल के राष्ट्रीय अन्तर्मित आने वाली चुनौतीयों से कैसे निपट सकेगा।

नवम्बर, 2019 में जब नेपाल में ओली की सरकार थी, उस वक़्त कालापाणी इलाके पर नेपाल ने दो टक़ कह

दिया था कि भारत को इस क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। उस वक्त भी सवाल उठा था कि आती की आक्रमक भाषा के पीछे कहीं तीन मनस्सें तो काम नहीं कर रहे। हालांकि, 2014 में नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान तकालीन नेपाली राष्ट्रपति कोइराला ने कालापाणी का मुद्दा उठाया था और कलापाणी पर नेपाल का अधिकार बताया हुए इसे हल करने की अपील की थी। 1996 में कालापाणी इलाके के संयुक्त विभाग के लिए महाकाली संघ के तुरंत बाद नेपाल की

विचार मंथन

# सरकार के निर्णयों पर न्यायपालिका सोच बदले?

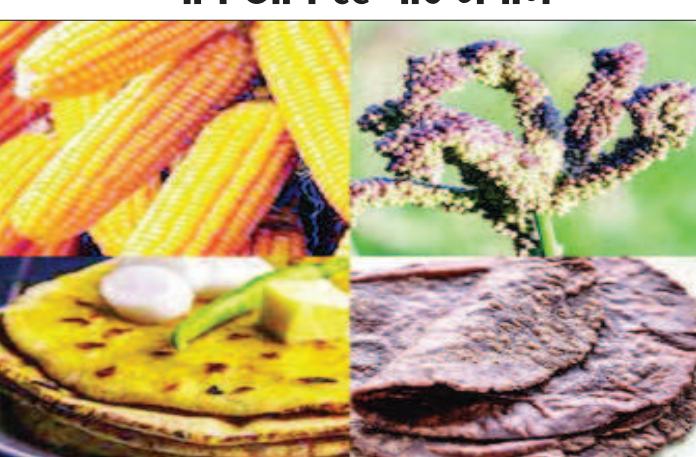


सरकार के ऊपर होती है। सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका के मंत्री और अधिकारियों की लोक संपर्क के रूप में सविधान ने जिम्मेदारी तय की है। विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं। वह संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले नहीं होने चाहिए। जो भी नियम कानून लाया होता है। वह संविधान के अनुरूप हो देखना का अधिकार केवल न्यायपालिका का है। न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी। उसे मानने की बाध्यता विधायिका ओर कार्यपालिका के लिए संविधान ने तय करके रखी है। पिछले वर्ष में विधायिका ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो नारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले थे। उन्हें न्यायपालिका ने सम्पर्क - सम्पर्क पर निरस्त किया। इसके साथ ही

सरकार और उसके अधिकारियों ने गाइडलाइन के माध्यम से ऐसे नियम तयार किए जिनमें आम आदिमयों का उचीड़न और स्वतंत्रता बाधित हुई। ऐसे सभी मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार न्यायपालिका के पास है। सरिवाहन को यदि यह विश्वास होता कि जनप्रतिनिधि जो भी कानून बनाएंगे वह सरिवाहन के अनुरूप होंगे। वह जा भी कार्य कराएंगे और प्रारंभिक और मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। फिर न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं ठीक। सबसे बड़े आश्वय की बात यह है कि न्यायिकों में जो 5 करोड़ मामले लटकते हैं। उनमें 70 से 80 फीसदी मामलों में

मंदस

## ध्यान खींच रहे मोटे अनाज



www.ijerpi.org

में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। सवाल अहम यह है कि भारत सहित दुनिया के देश मटे अनाज की खेती पर जोर वडों दे रहे हैं? जबाब स्पष्ट है, तेजी से ही रहा जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या चिंता की बात है, ऐसे में फसलों के उत्पादन में कमी आएगी और खाद्य पदार्थों की मात्रा में बढ़ोत्तरी जिसके कारण सभी के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना बड़ी चुनौती हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भवित्व में सूखा और अकाल पड़ने जैसी घटनाएं सामान्य हो जायगी। मात्र अनाजों की खेती करके

सकता है। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। भारत दुनिया के कई देशों को मोटे अनाज का नियांत करता है। इनमें सबसे अख अमेरिका, नेपाल, सऊदी अरब, लिबिया, अमान, मिस्र, टह्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन तथा अमेरिका शामिल हैं। मोटे अनाजों में भारत सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार और कुट्टु को एक्सपोर्ट करता है। वैष्णव उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में बाजरा के अग्रणी उत्पादकों में शुमार है।

कम्पनिस्ट पार्टीटों ने कालापाणी पर दावा करना शुरू कर दिया। उधर, चीन लंबे समय से इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। चीन की शह पर ही नेपाल में जब-तक कालापाणी को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। एक बीज जाग है जहाँ भारत 1962 के युद्ध में चीन के समक्ष मजुरानी से डटा था। आपको डर है कि अगर कालापाणी नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया तो चीन वहाँ अपने पांव जमा लेगा। भारत की धेराबदी में जुटे चीन की भी यही मस्ता है।

चीन की महावाराकांड परियोजना बन बैठ बन रोड में सहयोगी होने और व्यापारिक हितों के कारण नेपाल का झुकाव भारत से कहीं अधिक चीन की ओर है। नवम्बर, 2019 में पीएम मोदी ने काठमांडू में हुई बिस्मिटेक देशों के समान सेव्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा तो ऐन वर्त पर चीन के दबाव में नेपाल ने सेव्य अभ्यास में शामिल होने से इंकार कर दिया। जबकि बाक में उसने सीनों का साथ सेव्य अभ्यास में भाग लिया था। भारत और नेपाल के बीच भारतीय सेना की गोरखा बटालियन में गोरखा सीनिकों की भर्ती के मुद्दे पर भी तनातीरी की स्थिति बनी हुई है। नेपाल नाराज है कि भारत सरकार ने सेना में भर्ती की अपनीनथ योजना को लेकर उससे वर्ता तक नहीं है। नेपाली विदेश मन्त्री नारायण खड्गको नेपाल में भारतीय राज्यटूट नवीन श्रीवास्तव से मिलकर इस योजना के तहत नेपाली युवकों की भर्ती की योजना को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं।

नेपाल का आरोप है कि अग्रिमपथ योजना नवमदर, 1947 में भारत-ब्रिटेन एवं नेपाल के बीच हुए विधिक्षण समझौते का उल्लंघन है। हालांकि, भारत ने नेपाल को आश्रित किया है कि अग्रिमपथ योजना के सारे फायदे, जो भारतीय युद्धों को मिलेंगे, नेपाल के गोरखाओं को भी खाली हाथ होंगे। थल स्थान प्रस्तुत जनरल नोडोज पाडे की नेपाल की पांच दिवसीय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर नेपाली गोरखा अग्रिमदीर्घ बनने के लिए नहीं आते हैं, तो उनकी खाली जगह को भारत में रह रहे गोरखाओं से भरा जाएगा। अब तक 30 हजार से अधिक गोरखा भारतीय सेना में हैं। नेपाल में अग्रिमपथ योजना के तहत 1300 सैनिकों की भर्ती की जानी है।

हालांकि, भारत और नेपाल, दोनों स्वान संस्कृत और

मूल्यों वाले प्रारंभी हैं। इसके बाजूद दोनों देश के सबध निधिरित दायरे से बहार नहीं निकल पाए हैं, तो इसकी बड़ी जगह कहीं न कहीं नेपाल का चीन प्रेम ही है। आओं के समर्थन से बन रही नेपाल की नई सरकार भारत के साथ शिरों को किस तरह आग बढ़ाती है, यह अपाल कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

विरुद्ध न्यायालयों में लोग गए हुए हैं। यदि इन्हे बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ मुकदमे हैं। सरकार के अनुसार न्यायालीशों की नियुक्ति भी सरकार की मनमर्जी से होती। न्यायालीशों पर भी सरकार की मंथा के अनुरूप नियर्णय देने की बधाया होती। ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन ने नियर्णय किए हैं। उससे अलग हटके न्यायपालिका को काई नियर्णय न्यायपालिका नहीं कर पाएगी। संवैधानिक स्वास्थ्यों में जो नियुक्त हो रही है। उसमें सरकार के इसारे पर सरें नियर्णय हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविधान की मूल भावना और नागरिकों के मूल मौलिक अधिकार के सुरक्षित रह पाएंगे। चुनाव आयोग जांच जैसे एनाराई सीबीआई आधारक प्रवर्तन निवेशलाइ के इस्तदाद में जो नियुक्ति हो रही है। उनको लेकर लगातार प्रवर्तनबद्ध निवाचित जनपत्रिनिधियों द्वारा ही लापां जा रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे की बात देखने को मिल रही है। भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ भारतीय लिखित संविधान के अनुसार ही नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति उनकी योग्यता निष्पक्ष संविधान के प्रति निश्चिट रही ही जरूरी है। भारत में अनादिकाल से चले आ रहे ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिकारिता के तहत जो भारतीय संविधान तेजार किया गया है। उसे कायम रखा जा सकता। अपने आपको संवैधान की कोशिका करेगा उससे भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रख पाना सभव नहीं होगा। कार्यालीका तथा विधायिका की तानाशही बढ़ती उस पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। जो आज सत्ता में है वह कल विपक्ष में होंगे। कानून का राज

बेकरी, ब्रैकफास्ट, रेडी टू इंट फॉड, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, वेटरीज और पशु आहार बेवरकर चीन दूनिया में मोटी कम्हई कर रहा है। वह तब है जब वह दुनिया का मात्र 9 फीसदी ही मात्रा अनाज पैदा करता है। खेत, केंद्र सरकार ने बाजार सहित सभाधित उत्तरांचल के नियर्यात को बढ़ावा देने तथा पोषण अनाजों की आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए पोषक अनाज नियंत्रण सर्वधन फोन्स का गठन किया है। मोटे अनाज की कैटरोपी में ज्वार, बाजरा, रागी (मुडाऊ), जौ, कादी, सामा, बाजरा, सांवा, कुट्टोंगी, कोंगनी और चीना जैसे अनाज आते हैं। इन अनाजों के सेवन से मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप-2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाते हैं। इनमें कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। मोटे अनाज में सिर्फ़ फाइबर ही नहीं, बल्कि विटामिन-भी, फालेट, असायरन, असायरन, मैनीशियम, असायरन और कई तरह के

एंटीऑक्साइडेंट्स पाए जाते हैं। मोटे अनाज जहां सेहत के लिए रामबाण हैं तो दूसरी तरफ खेती करने वाले किसानों के लिए भी काफ़ा योगदान हैं। मोटे अनाजों की खेती करके जलवाया परिचर्तन, ऊर्जा संकट, भू-जल हासि, और खाद्यान्न संकट जैसी समस्याओं को कानून में किया जा सकता है। हम उपर्याद कर सकते हैं कि भारत 2023 में जी-20 की अधिकाता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के डेस्ट्रेयों और लक्षणों के मद्देनजर देश और दून्या में मोटे अनाजों के लिए जागरूकता पैदा करने में सफल होगा। और इससे मोटे अनाज का वैशिष्ट उत्पादन बढ़ागा, मोटे अनाज का वैशिष्ट उत्पादन बढ़ागा। साथ ही, कृषक प्रसंस्करण एवं फसल बच्च का बढ़तर उत्पादन सुनीचित होगा। भारत द्वारा वर्ष 2023 में मोटा अनाज वर्ष के तहत मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता की प्रभावी रणनीति से एक बार फिर मोटे अनाज को देश के हर वाहिं की थाली में अधिक जगह मिलने चाहिए।







